भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2116
मंगलवार, 14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण

†2116. श्री तापिर गाव:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;
(ख) डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप इसमें क्या परिवर्तन देखे गए हैं; और
(ग) उपरोक्त से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं,

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): 13 करोड़ किसान सदस्य आधार के साथ लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS)/लार्ज एरिया मल्टी-पर्पज़ समितियां (LAMPS) हैं । 2,516 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में 63,000 कार्यशील पैक्स/ LAMPS के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ आधारित प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में साथ लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ा जाएगा ।

वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 54,752 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 201.18 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी की राशि हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए जारी किया गया है । इस परियोजना के अधीन कंप्यूटरीकरण हेतु सिफारिश किए गए पैक्स के राज्य-वार ब्यौरा ***अनुबंध*** के रूप में संलग्न है । नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयां (PMUs) की स्थापना हो चुकी हैं । नाबार्ड द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तर की परियोजना सॉफ्टवेयर वेंडर (NLPSV) द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण आरंभ हो चुका है । सिस्टम इंटिग्रेटरों (SIs) को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है तथा शीघ्र ही सिस्टम इंटिग्रेटरों की सूची राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साझा की जाएगी ।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण से विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे जैसे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होगा, लेनदेन दरों में कमी आएगी, भुगतानों के असंतुलन में कमी आएगी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन होगा तथा पारदर्शिता में वृद्धि होगी । कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट सूचना सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स अपने कार्यों को ऑनलाइन कर सकेंगे और अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन/ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

*****

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कंप्यूटरीकरण हेतु सिफारिश की गई पैक्स की संख्या
	राज्य	
1	आंध्र प्रदेश	2,037
2	अरुणाचल प्रदेश	14
3	असम	583
4	बिहार	2,223
5	छत्तीसगढ़	2,028
6	गोवा	44
7	गुजरात	5,754
8	हरियाणा	662
9	हिमाचल प्रदेश	870
10	झारखंड	1,500
11	कर्नाटक	5,491
12	मध्य प्रदेश	4,534
13	महाराष्ट्र	12,000
14	मणिपुर	232
15	मेघालय	85
16	मिज़ोरम	25
17	नागालैंड	33
18	पंजाब	3,482
19	राजस्थान	1,963
20	सिक्किम	107
21	तमिल नाडु	4,478
22	त्रिपुरा	268
23	उत्तर प्रदेश	1,539
24	पश्चिम बंगाल	4,167
	संघ राज्यक्षेत्र	
1	अंडमान और निकाबार द्वीपसमूह	41
2	जम्मू और कश्मीर	537
3	लद्दाख	10
4	पुड्डुचेरी	45
	कुल	**54,752**